



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 2018/श्रावण 19, 1940

No. 275]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 2018/SHRAVANA 19, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

मामला सं. एसएसआर-16/2018

विषय : चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एलमुनियम अलॉय रोड बिल (एआरडब्लू)' के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरूआत

फा. सं. 7/31/2018-डीजीटीआर.—वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और थाइलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एलमुनियम अलॉय रोड बिल (एआरडब्लू)' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में दिनांक 11 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना सं 15/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी जांच की शुरूआत की और जिसे बाद में अंतिम जांच परिणाम सं 14/7/2012-डीजीएडी दिनांक 9 जून, 2014 पर आधारित दिनांक 2 मई, 2015 एमओएफ अधिसूचना सं. 21/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा 5 वर्षों के लिए लागू किया गया था। तथापि, डब्लूपी 633/2015, डब्लूपी 634/2015 आदि में प्राकृतिक न्याय के आधारों पर दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय डीबी द्वारा अंतिम जांच परिणाम 4722 GI/2018

सं. 14/7/2012-डीजीएडी को खारिज किया गया। तथापि, उक्त निर्णय पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी (सी) सं. 014068 – 014073/2015 द्वारा स्टे दिया गया और उक्त एसएलपी अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है। एमओएफ अधिसूचना सं. 21/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 22 मई, 2015 को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टे के बाद जारी किया गया और अधिसूचना इस समय लागू है।

2. यतः मै. सिनर्जीज कास्टिंग्स लि. और मै. कोसेइ मिंडा एलमुनियम कंपनी लि. (जिन्हे आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) ने संयुक्त रूप से उक्त अधिनियम और नियम के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत रूप से साक्षात्कृत याचिका दायर की है जिसमें चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे आगे पांच वर्षों तक लागू रखने का अनुरोध किया गया है।

### शामिल देश

3. वर्तमान निर्णयिक समीक्षा जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और थाइलैंड हैं।

### विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. वर्तमान एसएसआर जांच में विचाराधीन उत्पाद मोटर वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले 12 इंच से 24 इंच के बीच के व्यास के आकार के कास्ट एलमुनियम अलॉय रोड व्हिल या अलॉय रोड व्हिलस (एआरडब्लू) हैं जिन्हें अपने अनुषंगियों के साथ लगे हों अथवा नहीं। 12 इंच से 24 इंच से इतर व्यास के और मोटर वाहनों से इतर के प्रयोग के एआरडब्लू उत्पाद के दायरे से बाहर हैं। वस्तुओं में तैयार और अर्द्धनिर्मित एआरडब्लू शामिल हैं जिन्हें अनपेटेड, पेटेड या क्रोम प्लेटेड हों। एआरडब्लू का मुख्य कार्य यह है कि इन्हें वाहन को चलाने के लिए मोटर वाहनों में लगाया जाता है। मोटर वाहनों के पहियों को आम तौर पर स्टील या एलमुनियम अलाय स्टील से बनाया जाता है ये पहिये उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं हैं।

5. एआरडब्लू को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 87 के अंतर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं. 8708.70 के अंतर्गत 'रोड व्हिल एंड पार्ट्स और एसेसरीज देयरआफ' वर्णन के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है, संबद्ध वस्तु का अयात विभिन्न सीमाशुल्क वर्गीकरणों जैसे 87087000, 87082900, 87089900, 87149290, 87149990, 87089400 आदि के अधीन भी आयात किया जा रहा है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

### समान वस्तु

6. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं हैं परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

7. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद मापदंडों जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के अनुसार तुलनीय विशेषताओं वाले हैं। यह याचिका समीक्षा और लागू शुल्क को जारी रखने के लिए दायर की गई है और समान वस्तु के मुद्रे पर पहले ही पूर्ववर्ती जांचों में विचार किया गया है। मूल जांच में प्राधिकारी ने पहले ही यह माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु हैं।

### **घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

8. यह याचिका मै. सिनर्जीज कास्टिंग्स लि. और मै. कोसेर्इ मिंडा एलमुनियम कंपनी लि. द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।
9. भारत में संबद्ध वस्तु के दो और उत्पादकों अर्थात् मै. मिंडा कोसेर्इ एलमुनियम व्हिल्स प्रा. लि. और मै. निओ व्हिल्स लि. ने याचिका का समर्थन किया है। याचिकाकर्ताओं और उनके समर्थकों का याचिका के अनुसार कुल भारतीय उत्पाद में 62.30 प्रतिशत हिस्सा बनता है।
10. यह देखा गया है कि याचिकाकर्ताओं का उत्पाद संयुक्त रूप से कुल भारतीय उत्पादन का 40.29 प्रतिशत है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु के अधिकांश हिस्से के उत्पादक हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं।

### **पाटनरोधी शुल्क की निर्णायिक समीक्षा की शुरुआत**

11. यतः याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार एक विस्तृत याचिका दायर की है, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायिक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं ताकि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

### **जांच अवधि**

12. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2017 – 31 मार्च, 2018 तक (12 महीनों) की है। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2014 – मार्च 2015, अप्रैल 2015 – मार्च 2016, अप्रैल 2016 – मार्च 2017 और जांच की अवधि शामिल होगी। पाटन और क्षति की संभावना के निर्धारण के लिए जांच अवधि के बाद की अवधि के आकड़ों की भी जांच की जा रही है।

### **प्रक्रिया**

13. वर्तमान निर्णायिक समीक्षा में अधिसूचना सं. 14/1/2011-डीजीएडी दिनांक 9 जून, 2014 (मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम) के सभी पहलू शामिल हैं।
14. संबंधित नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

15. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**वाणिज्य विभाग**

**व्यापार उपचार महानिदेशालय**

**चौथा तल , जीवन तारा बिल्डिंग ,**

**5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

**[dgad.india@gov.in](mailto:dgad.india@gov.in)**

16. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उक्त अनुरोध का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा।

### समय-सीमा

17. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार, जिसका पता उपलब्ध नहीं है, भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

### गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध के किसी भाग के संबंध में “गोपनीयता” का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय अंश (सीवी) की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय अंश (एनसीवी) की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है/ ऐसी सूचना का सारांशीकृत क्यों नहीं किया जा सकता है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समूचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्वजनिक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साध्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

**असहयोग**

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

**सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक**

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**  
**INITIATION NOTIFICATION**  
New Delhi, the 10th August, 2018  
**Case No. SSR – 16/2018**

**Sub: - Initiation of Anti-Dumping Sun Set Review investigation concerning imports of “Aluminium Alloy Road Wheels (ARWs)” originating in or exported from China PR, Korea RP and Thailand.**

**F. No. 7/31/2018-DGTR.**— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter also referred as the Authority) initiated anti-dumping investigation on imports of “Aluminium Alloy Road Wheels” (hereinafter also referred as the subject goods), originating in or exported from China PR, Korea RP and Thailand (hereinafter also referred as the subject countries) vide Notification No. 15/2015-Customs (ADD) dated 11<sup>th</sup> April, 2014 and which was later applied for 5 years vide MOF notification No. 21/2015-Customs (ADD) dated 2<sup>nd</sup> May, 2015 based on Final Finding No 14/7/2012-DGAD dated 9<sup>th</sup> June, 2014. However, the Final Finding No 14/7/2012-DGAD was quashed by Hon’ble DB of Delhi HC on grounds of natural justice in WP633/2015, WP 634/2015 etc. However, a stay on the said judgment was granted by Hon’ble SC in SLP(C) No. 014068 - 014073 / 2015 and the said SLPs are pending final hearing. MOF notification No. 21/2015-Customs (ADD) dated 22<sup>nd</sup> May, 2015 was issued after stay by SC and the notification is currently in force.

2. Whereas, M/s Synergies Castings Ltd and M/s Kosei Minda Aluminium Company Ltd. (hereinafter referred to as ‘petitioners’) have jointly filed a duly substantiated petition before the Authority, in accordance with the Act and the Rules alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR, Korea RP and Thailand and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the present anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, for another five years.

**Country Involved**

3. The subject countries in the present sunset review investigation are China PR, Korea RP and Thailand.

**Product under Consideration and Like Article**

4. The product under consideration in the present SSR investigation is “Cast Aluminum Alloy Wheels or Alloy Road Wheels” (ARW) used in Motor Vehicles, whether or not attached with their accessories, of a size in diameters ranging from 12 inches to 24 inches. ARWs other than 12 inches to 24 inches’ diameter and for use other than motor vehicles are out of the product scope. The goods include finished or semi-finished ARWs whether unpainted, painted or chrome plated. The main function of ARWs is that they are fitted on motor vehicles to enable vehicle movement. Wheels for Motor Vehicles are generally made of Steel or Aluminium Alloy Steel wheels are not included in the product scope.

5. ARWs are classified under Chapter 87 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading No. 8708.70 under the description “Road wheels and parts and accessories thereof”. As claimed by the domestic industry, the subject goods are also imported under different customs classifications such as 87087000, 87082900, 87089900, 87149290, 87149990, 87089400 etc. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

**Like Article**

6. Rule 2(d) with regard to ‘like article’ provides as under: -

*“‘like article’ means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;”*

7. Petitioners have claimed that there is no known difference in subject goods produced by them and exported from the subject countries. The product under consideration produced by the petitioners and imported from the subject countries are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The petition filed is for the review and continuation of the anti-dumping duties in force, and the issue of like article has been already dealt with in the previous investigations. In the original investigations, the Authority has already held that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the same imported from the subject countries.

**Domestic industry & Standing**

8. The petition has been filed by M/s Synergies Castings Ltd and M/s Kosei Minda Aluminium Company Ltd jointly. The petitioners have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any other producer/exporter of subject goods in the subject countries or any importer in India.

9. There are two more producers of the subject goods in India supporting the petition namely M/s Minda Kosei Aluminium Wheels Pvt Ltd and M/s Neo Wheels Ltd. The petitioners with their supporters hold about 62.30% share in the total Indian production as per the petition.

10. It is seen that the production of the petitioners is jointly 40.29% of the total Indian production. The petitioners are the majority producers of the subject goods in India and are eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Rules of Anti-Dumping Rules.

### **Initiation of Sunset Review of Anti-Dumping Duty**

11. Whereas the petitioner has filed a detailed petition in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset Review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

### **Period of Investigation**

12. The period of investigation (POI) is 1<sup>st</sup> April 2017 – 31<sup>st</sup> March 2018 (12 months) for the purpose of present investigation. The injury investigation period will however cover the periods April 2014 – March 2015, April 2015 – March 2016, April 2016 – March 2017 and the POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

### **Procedure**

13. The present Sunset Review covers all aspects of Notification No. 14/1/2011 -DGAD dated 9<sup>th</sup> June, 2014, (final findings of the original investigation).

14. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

### **Submission of information**

15. The known exporters in the subject countries, the government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**Government of India**  
**Ministry of Commerce & Industry**  
**Department of Commerce**  
**Directorate General of Trade Remedies**  
**4th Floor, Jeevan Tara Building**  
**5, Parliament Street, New Delhi – 110001**  
**[dgad.india@gov.in](mailto:dgad.india@gov.in)**

16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

### **Time Limit**

17. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date of publication of this notification.

### **Submission of information on confidential basis**

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a)marked as Confidential (with title, index, number of

pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "**confidential**" or "**non-confidential**" at the top of each page and accompanied with soft copies.

19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version (CV) and two (2) copies of the non-confidential version (NCV) must be submitted by all the interested parties.

20. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **Inspection of public file**

24. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

#### **Non-cooperation**

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. and Director General